भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1669

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि पहलों के परिणाम

1669. डॉ. संबित पात्राः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री राव राजेन्द्र सिंहः
श्री शशांक मणिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2025 में आरंभ की गई या जारी रखी गई एग्रीस्टैक, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, नमो ड्रोन दीदी योजना, किसान ई-मित्र और अन्य डिजिटल कृषि पहलों के परिणामों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों का कवरेज कितना है तथा भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण की स्थिति क्या है और ऋण, बीमा और वास्तविक समय परामर्श सेवाओं तक पहुंच में कितना सुधार हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के लिए उत्पादकता, आय स्तर और बाजार लिंकेज पर इन पहलों के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी कवरेज है और क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): जी हाँ, सरकार वर्ष 2025 के दौरान प्रारंभ की गई या जारी रखी गई डिजिटल कृषि पहलों के परिणामों का लगातार मूल्यांकन करती है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

(I) एग्रीस्टैक: एग्रीस्टैक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल अर्थात् किसान रजिस्ट्री, जियो-रेफसरेंस्ड विलेज मैप्स और बोई गई फसल रजिस्ट्री हैं। इन सभी का निर्माण और रख-रखाव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। यह किसानों की पहचान, भूमि और उनकी फसलों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत स्थापित करता है।

किसान आईडी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद, ऋण वितरण, इनपुट वितरण और आपदा राहत के सुचारू एकीकरण को सक्षम बनाती है। दिनांक 04.02.2026 तक, देश में 8.48 करोड़ से अधिक किसान आईडी जारी की जा चुकी हैं।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण से फसलों की खेत-स्तर पर फसलों की जानकारी प्राप्त करना और विभिन्न सीज़न में बुआई के पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाना संभव हुआ है, जिससे खरीद, इनपुट आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स के लिए साक्ष्य-आधारित योजना बनाने में मदद मिलती है। खरीफ 2025 में, डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) देश के 604 जिलों में 28.5 करोड़ से अधिक खेतों को शामिल करते हुए आयोजित किया गया है।

महाराष्ट्र ने योजना की आपूर्ति, आपदा राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित परामर्श और ऋण पहुंच प्रदान करने के लिए एग्रीस्टैक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसमें खरीफ 2025 की फसल हानि के लिए 89 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से

अधिक का अंतरण शामिल है। छत्तीसगढ़ ने एमएसपी आधारित धान खरीद के लिए किसान आईडी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को संस्थागत रूप दिया है, जिसमें एक ही सीजन में 32 लाख से अधिक किसानों को शामिल किया गया है, जिससे पारदर्शिता, फसल सत्यापन और एमएसपी भुगतान की समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

II. कृषि निर्णय सहायता प्रणाली: कृषि निर्णय सहायता प्रणाली एक जियो-स्पेशियल प्लैटफार्म है जो कृषि नियोजन और निर्णय लेने में सहायता के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके सैटेलाइट इमेजरी, मौसम, मिट्टी और फसल संबंधी आंकड़ों को एकीकृत करती है। यह फसल, मौसम और मिट्टी से संबंधित लक्षित सलाह विकसित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक मंच (वेब-पोर्टल) के रूप में कार्य करती है।

III. किसान ई-मित्र: यह एक वॉइस-बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस चैटबॉट है जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता के लिए विकसित किया गया है। यह समाधान 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता हेतु विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में, यह औसतन प्रतिदिन 8,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का समाधान करता है और अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं।

IV. राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली: जलवायु परिवर्तन के कारण फसल हानि का सामना करने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फसलों में कीट प्रकोप का पता लगाती है, जिससे समय पर स्वस्थ फसलों के लिए हस्तक्षेप संभव हो पाता है। वर्तमान में 10,000 से अधिक विस्तार कार्यकर्ता इस टूल का उपयोग कर रहे हैं, इससे किसान कीटों की तस्वीरें ले सकते हैं और कीट संक्रमण कम करके फसल हानि को रोक सकते हैं। वर्तमान में, यह 65 फसलों और 400 से अधिक कीटों को कवर करती है।

V. नमो ड्रोन दीदी: सरकार ने 'नमो ड्रोन दीदी' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है ताकि दक्षता में सुधार हो, फसलों की पैदावार बढ़े और परिचालन लागत कम हो। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को आय वृद्धि और आजीविका सहायता प्रदान कर ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त बनाना है। प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 ड्रोन वितरित किए हैं। एग्रीकल्चरल डेवलप्मेंट एंड रूरल ट्रांस्फॉर्मेशन सेंटर (एडीआरटीसी), बेंगलुरु ने इन 500 ड्रोनों के संचालन की आर्थिक और व्यावसायिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चलता है कि ड्रोन को अपनाने से स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों में विविधता आई है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के लिए आय के अवसरों में वृद्धि हुई है।

VI. सीड ऑथेंटिसिटी ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी (साथी): यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में बीज उत्पादन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, वितरण और अखिल-भारत ट्रेसेबिलिटी के समग्र प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। इस प्रयास के तहत एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड (एनएसजी) स्थापित किया गया है, जो सभी बीज स्टेकहोल्डर्स को एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के भीतर शामिल करता है।

******